IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में नक्सलवाद की समस्या एवं चुनौती

रंजीत सिंह
शोध छात्र–मालवीय सेन्टर फॉर पीस रिसर्च
सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सारांश

यद्यपि नक्सलवाद का वास्तविक उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता स्थापित करना है, किन्तु अकारण हिंसा, अपराध एवं उग्रवाद अपनाने के कारण यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर चुनौती एवं सुरक्षा की दृष्टि से एक सामयिक समस्या के रूप में उभरा है। सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राजसत्ता पर अधिकार करने के उद्देश्य स्वयं समाज राज्य एवं राष्ट्र के अस्तित्व के लिए घातक है। हिंसा भले ही एक सीमा तक प्रभावी हो सकती है लेकिन इस तरह के आतंक से राजव्यवस्था नहीं बदली जा सकती। राजभक्ति के सामने इनकी कोई बिसात भी नहीं है। वंचितों के हितों की रक्षा के लिए यह बेहतर होगा कि नक्सली लोकतंत्र की सीमाओं में रहकर ही इन्हें संचालित करने का प्रयास करें। यह स्वयं उनके एवं राष्ट्र के हित में होगा।

मुख्य शब्द : वर्ग संघर्ष, सामन्तवाद, साम्यवाद पीपुल्स वार ग्रुप, अराजकतावाद, रैयत कुली संघ, रेडिकल स्टूडेन्ट यूनियन, रेडिकल यूथ लीग, विप्लवी रचियता संघम, जन नाट्य मण्डली, माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर (MCC)।

प्रस्तावना

भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है। ज़मींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था; इसीलिये इसे माओवाद भी कहा जाता है और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मज़दूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। इसलिए वह अपने पुरातन काल से ही अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। इसी का परिणाम है कि उसने अपने लिए एक समाज व्यवस्था का निर्माण किया है। लेकिन इस समाज व्यवस्था में विषंगतियां पैदा होती रही है। नक्सलवाद भी समाज की एक ऐसी ही विषंगती का परिणाम है।

साहित्यावलोकन

प्रथम चरण (1967 से 1980 तक): इसका प्रथम चरण मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवाद पर आधारित था। इसका मतलब ये ''वैचारिक और आदर्शवादी'' आंदोलन का चरण रहा है। इस चरण में नक्सलवादियों को ''ज़मीनी अनुभव तथा अनुमान की कमी''देखने को मिली। इस चरण में नक्सलियों को एक ''राष्ट्रीय पहचान'' मिली लेकिन वे एक राष्ट्रीय प्रभाव नहीं डाल पाए।

18 मार्च 1967 से जारी इस सशस्त्र गतिविधि को 1971 तक सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। इसके बचे नेताओं को भूमिगत होकर काम करना पड़ रहा था। आपातकाल के दौरान् नक्सली आंदोलन खत्म हो गया था। इसके अधिकांश नेता जेल में बंद हो चुके थे।

दूसरा चरण (1980 से 2004 तक): ये दौर ज़मीनी अंदाज़ा, ज़रुरत और अनुभव के आधार पर चलने वाला क्षेत्रीय नक्सली गतिविधियों का दौर था। इस चरण में नक्सलवाद का व्यवहारिक विकास हुआ। इनका क्षेत्रीय प्रभाव और विस्तार भी देखने को मिलता है।

तीसरा चरण – (2004 से जारी) : इस चरण में नक्सलियों का ''राष्ट्रीय स्वरूप'' उभरा और ''विदेशी संपर्क'' बढ़े। और अब नक्सलवाद राष्ट्र की ''सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती''बनकर उभरा।

साल 2004 नक्सली संघर्ष की सैन्य और राजनीतिक ताकत और जनाधार के प्रदर्शन का साल रहा। इस दौरान संसदीय जनतंत्र के ख़िलाफ चुनाव बहिष्कार और नक्सलियों का दक्षिण एशिया के सशस्त्र वामपंथी संगठनों के बीच बढ़ते समन्वय को भी देखा जा सकता था।

देश की नक्सली राजनीति में भी साल 2004 में एक नया मोड़ तब आया जब पीपुल्सवार और एमसीसीआई का एकीकरण हुआ और एक नई पार्टी बनी– भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य में नक्सलवादी आंदोलन एक गंभीर चुनौती के रूप में मौजूद। इस आंदोलन का आरंभ पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी के एक संभाग से हुआ जिसमें नक्सलवादी, पंसीदेवा, व खरीवाड़ी जैसे तीन उपक्षेत्र थे। इसमें संथाल, ओराव तथा राजवंशी जैसी जनजातियों के लोग रहते हैं। इसी नक्सलवाडी क्षेत्र के कारण इसका नाम नक्सलवाद पड़ा। नक्सलवाडी गाँव में भूस्वामियों के विरूद्ध भूमिहीन किसान व बेरोजगार युवकों ने अपना संघर्ष अभियान आरम्भ किया। इस संघर्ष को मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (1964) सदस्य एवं जिला स्तरीय नेता चारू मजूमदार, कानू सान्याल व जंगल संथाल ने नेतृत्व प्रदान किया। नक्सलवादी विचार को सैद्धांतिक समर्थन अप्रैल 1969 में मिला, जब चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की नवीं कांग्रेस सम्पन्न हुई, जबकि माओं के विचार को मार्क्सवाद लेनिनवाद की चरम सीमा कहा जाता था। इन्हीं विचारों का उपयोग करते हुए नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार ने घोषणा की थी कि चीन का चौयरमैन हमारा चौयरमैन है। बंगाल से नक्सलवादी आंदोलन भूमिहीन श्रमिकों की ओर से संघर्ष के रूप में बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व आन्ध्रप्रदेश में फैला। स्वाधीन भारत के इतिहास में नक्सलवादी आंदोलन मात्र एक किसान एवं भूमिहीन वर्ग की जागृति का ही एक आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हेतु कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों ने चीन में हुई कम्युनिस्ट क्रांति से सबक सीखते हुए लेनिनवाद, मार्क्सवाद और माओत्से तुंग विचारधारा को अपना प्रस्थान बिन्दु माना। सामन्तवाद को समाप्त करने हेतु साम्यवाद का संघर्ष उस समय उग्र हुआ, जब भूमिहीन किसान एवं अपेक्षित सामाजिक

वर्ग ने इसका दामन थाम लिया। राज्य प्रशासन द्वारा अभूतपूर्व दमन, दबाव एवं उत्पीडन के बावजूद नक्सलवादी गतिविधियों का सिलसिला आज भो जारी है। नक्सलवाद अपने मूल स्थान पश्चिमी बंगाल में तो पनप नहीं सका, लेकिन जहाँ नक्सलवादियों के छिपने एवं कूट योजना बनाने हेतु जंगल एवं घाटी क्षेत्र विशेष रूप से उपलब्ध हैं, वहाँ अधिक पनपा और आज भी इसका आतंक कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है जैसे आंध्रप्रदश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, छत्तिसगढ़ एवं झारखण्ड आदि।

आज नक्सलवादी संगठनों के पास कुशल सूचना तंत्र, विशेष प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली भी है। नक्सलवादी नाम से आमतौर पर प्रचलित कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की यह धारा स्पष्ट तौर पर दो प्रवृत्तियों के बीच वर्तमान मेंविभाजित द्य एक विशेष रूप से आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एवं उड़ीसा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रिय पीपुल्सवारग्रुप जो नक्सलवाद की अराजकतावादी धारा। दूसरी प्रवृत्ति जो संसदीय व गैर संसदीय संघर्ष को अपना प्रस्थान बिन्दु मानती है। उसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन यानि भाकपा (माले) लिबरेशन कहा जाता है। आंध्रप्रदेश के नक्सली नेता कोडापल्ली सीतारमैया ने तमिलनाडु के नक्सली नेता कोदंडरामन के साथ मिलकर पीपुल्स वार ग्रुप का गठन किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी विचारधारा स जोड़ने व ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए पीपुल्स वार ग्रुप ने रैयत कुली संघ स्थपित किया, जबकि शहरों में सक्रियता बनाये रखने हेतु उन्होंने रेडिकल स्टूडेन्ट यूनियन तथा रेडिकल यूथ लीग स्थापित किये। इसके साथ ही नागरिक अधिकार संगठन आंध्रप्रदेश सिविल लिबर्टी कमेटी में उसने अपना शक्लिशाली आधार स्थापित कर लिया। सांस्कृतिक क्षेत्र में इस संगठन ने विप्लवी रचियता संघम और जन नाट्य मंडली का गठन करके लोकप्रियता की एक क्रांति उत्पन्न कर दी। इसके फलस्वरूप मध्यम वर्गीय युवक एवं गरीब व उपेक्षित वर्ग विशेष रूप से इससे आकर्षित होने लगा आर आंध्रप्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र के गडचिरौली और चंद्रपुर तक अपना विस्तार कर लिया। तेलंगाना आज एक स्वतंत्र राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में भी इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होने लगा। बस्तर आज छत्तीसगढ़का भाग है। बिहार में विशेष रूप से सक्रिय पार्टी यूनिटी ग्रुप का इस संगठन में विलय हो गया। पीपुल्स वार ग्रुप की तरह बिहार का एक नक्सलवादी गुट माओवादी कम्यूनिस्ट सेन्टर (M.M.M.) भी इस समय खासतौर से सक्रिय है।

पीपुल्स वार ग्रुप के तरत नक्सलवाद ने उत्पीड़न उन्मूलन के लिए खुले संगठनों की आड़ में अपने छापामार दलों को अपने नियमित सेना की भांति संरचनाओं में संगठित कर रखा है। श्रीलंका के एल.टी.टी.ई. छापामार दल की तरह भूमिगत बारूदी सुरंगें बिठाने में विशेष रूप से दक्षता प्राप्त कर रखी है। इसी कौशल के तहत ही आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर हमला करके पीपुल्स वार ग्रुप ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को एक सीधी चुनौती दी। एक लम्बी अवधि के हथियारबन्द यह ग्रुप इस घटना के बाद चर्चित अवश्य हो गया है, किन्तु पीपुल्स वार ग्रुप एक कुशल नेतृत्व के अभाव में अपना अभी तक ठोस सामयिक आधार स्थापित नहीं कर पाया है और न ही अपने निर्धारित लक्ष्य को पा सका । ऐसे पीपुल्स वार ग्रुप विगत दो दशकों से सबसे बड़ी नक्सली शक्ति के रूप में उभरता नजर आ रहा है।

भारत के विभिन्न राज्यों में नक्सलवादी हिंसा की समस्या चार दशक से भी अधिक समय से चली आ रही है, किन्तु इन समस्याओं को उखाड़ फेंकने का सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किया गया है जिससे यह चुनौती उत्पन्न हुई है। भूमिसुधार नियमों पर बेमन से अमल आदिवासी जन कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित जर्जर आम जनता या फिर भोले—भाले आदिवासियों की जमीनों को ओने—पौने दामां में खरीदने की गैर आदिवासियों की कोशिश,

जबकि संविधान में इस तरह के क्रय–विक्रय पर पूरी तरह रोक है। व्यवहार में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भूमि लागू होने के बावजूद फालतू जमीन भूमिहीनों को नहीं दी कानून के गयी और कानून के संरक्षकों ने जमीन मालिकों का ही साथ दिया, यही हाल आदिवासी जनकल्याण योजनाओं का नाम मात्र लाभ ही जरूरतमंद आदिवासियों के हाथों साधते हैं। तक जाने दिया तथा इनकी हकमारी की गयी।

वस्तुतः नक्सली माफिया गिरोह की भांति सिर्फ अपराध के लिए जीवित रहने वाले अपराधी नहीं है। इसकी एक विचारधारात्मक पृष्ठभूमि होती है और वह प्रायः किसी और अपराधिक संयुक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु ऐसे काम को अंजाम देते हैं। यह दूसरी बात है कि समय के साथ सोच–विचार और संयुक्त लक्ष्य जैसी बातें महत्वहीन हो गयी हैं और इन नक्सलवादी गुटों के लिए हिंसा, आतंक, निजी स्वार्थ एवं प्रतिशोधात्मक कार्यवाहियाँ ही प्रमुख माफिया गिरोहों में तब्दील हो गए हैं, जिनका काम आतंक फैलाकर रकम वसूलना रह गया है। इन संगठनों का सहारा लेकर बहुत से अपराधी इसमें घुस गये हैं। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, जिनका एकमात्र उद्देश्य अराजकता पैदा करके धन कमाना होता है। इसी के बहाने वे लूटपाट, अपहरण और अपराध करके पैसे की उगाही करते हैं। वे इस आंदोलन की आड़ में अपना हित साधते है।

इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि धोखाधड़ी से आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करके उनके सामने रोजी रोटी का विकराल सवाल खड़ा कर दिया गया है। वास्तव में नक्सलवादी पनपने का एक प्रमुख कारण समाज में व्याप्त वर्गभेद के साथ गरीबी एवं बेराजगारी भी है। अतः आवश्यक है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों पर ईमानदारी और तेजी के साथ अमल हो, क्योंकि गरीब एवं बरोजगार युवकों को अतिवादी गुट बड़ी आसानी से गुमराह करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि प्रशासन, पुलिस व समाज के लोगों को अपना शत्रु समझें। इस प्रकार अराजकतावादी तत्व बेरोजगार युवकों को गुमराह कर हिंसा एवं आतंक की ओर प्रेरित करते हैं। आज के सक्रिय नक्सलियों में तरह–तरह के चेहरे–मोहरे के लोग शामिल हैं। उनमें से कुछ का मतलब अपने जातीय हितों की रक्षा करना है तो कुछ हथियारबंद दहशतगर्दी से फिरौती, उगाही एवं रंगदारी का चस्का लग चुका है। लेवी के रूप में वसूली, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से दुश्मनी, खुद अपराध तय करना और खुद दण्ड निर्धारित करके दोषी का फैसला कर देना, इन लोगों की दिनचर्या बन गया है।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 1 मई 2019 को माओवादी द्वारा विस्फोट किया गया। दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल (SATP) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष देशभर में माओवादी संबंधित हिंसा की 53वीं घटना थी। गढ़चिरौली सहित 2019 में अब तक देश भर में वामपंथी उग्रवाद से जुड़ी हिंसा में कम से कम 107 लोग मारे गए हैं, जहाँ हाल के वर्षों में सबसे बड़ा हमला हुआ और पुलिस की त्वरित जिम्मेदार टीम के 15 सदस्यों की मौत हुई और निजी वाहन में यात्रा करने वाला ड्राइवर।

पाँच वर्षों से अप्रैल तक नक्सली/माओवादी हुए हैं। इन हमलों में 451 लोक मारे गए हैं और 1589 लोग घायल हुए हैं। इसलिए देश को अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने की आववश्यकता है।

हाल के वर्षों में इस समस्या के समाधान के लिए नई दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में नक्सलवादी उग्रवादी को सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए इसका सफाया किये जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इसका सफाया होने तक शांति से नहीं बैठेंगे। इसी सम्मेलन में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार ने कहा कि नक्सलवाद अब आतंकवाद के समान ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। आज नक्सलवाद हमारे देश के लिए नासूर बन गया है। नक्सलवाद ने अपने प्रभाव क्षेत्र

में बड़े पैमाने पर छात्रों आर नौजवानों को संगठित किया है। सामाजिक व्यवस्था बदलने की भावना ने हजारों युवकों ने अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली है। जिन मुद्दों पर नक्सल आंदोलन आरम्भ हुआ था, वे मुद्दे यानि जमीन के अधिकार, भूख का मर्म व दर्द आज भी जिन्दा है।

केन्द्र सरकार ने निर्णय किया है कि आतंकवादी, उग्रवादी या नक्सलवादी हमले में मारे जाने वाले निर्दोष लोगों के परिवार वालों को आर्थिक मदद के लिए 5–5 लाख मुआवजा राशि का प्रावधान किया जाएगा। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुर्नवास योजना का लाभ दिया जाता है। कांग्रेस सरकार ने 2013 में भूमि सुधार कानून लागू करके भी काफी बढ़िया काम किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बीते कुछ वर्षों में नक्सलवादियों ने काफी संख्या में आत्मसर्पण किया है।

निष्कर्ष

वास्तव में नक्सलवाद एक जटिल एवं गंभीर समस्या के रूप में मौजूद है। वे गरीबी और पिछड़ेपन का दंश आजादी के बाद से ही झेल रहे हैं। ऊपर से बेरोजगारी और उद्योग शून्यता आदि ने युवकों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जिसका नतीजा यह हुआ कि नक्सली समस्या अब नासूर बन गयी है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभावित इलाकों की समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संभावनाएँ खत्म हो गयी है। बस सरकार योजनाबद्ध ढंग से काम करे और हिंसा का दमन करने के साथ बुनियादी समस्याओं का हल खोजे ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स एंजेल्स
2. राज्य और क्रान्ति–लेनिन
3. उग्र कम्युनिज्म एक बचकाना मर्ज
4. माओ की रचनाएँ (संग्रहित)
5. माओं की जीवनी–राहुल सांकृत्यायन
6- Mao: The Man and His Thought – R.N. Sharma
7- The New Class : An Analysis of the Communist India & Djilas Milevan
8- जनवरी 2019 दृष्टि IAS पत्रिका दिल्ली : क्या है नक्सली समस्या का समाधान
9. मार्च 2020 दृष्टि IAS पत्रिका दिल्ली : नक्सलवाद : कारण और निवारण